

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3224
उत्तर देने की तारीख 20.03.2025

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत आने वाले गांव

3224. श्री राजकुमार रोट:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएमजेयूजीए) के अंतर्गत अब तक जनजातीय बहुल क्षेत्रों में चयनित गांवों की संख्या कितनी है और उक्त से लाभान्वित हुए तथा लाभान्वित होने वाले गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त अभियान के अंतर्गत जनजातीय समुदायों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा अवसंरचना का विकास प्रदान किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अभियान के अंतर्गत बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के इंगरपुर-बांसवाड़ा में ग्राम पंचायत-वार कितने कार्य किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का बजट में वृद्धि करके उक्त अभियान के कवरेज का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग) प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार नाम) का 2 अक्टूबर, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के रूप में शुभारंभ किया गया है। अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को भरना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है, जिसमें बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के 1538 गांव शामिल हैं। इस अभियान के तहत गांवों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार कवरेज अनुलग्नक-I में है। अभियान के तहत प्रत्येक मंत्रालय को बजट और लक्ष्य आवंटित किए गए हैं और उन्हें सौंपे गए उपाय को लागू करना उनकी जिम्मेदारी है। अभियान का उद्देश्य अभिसरण और पहुंच (आउटरीच) के माध्यम से संतृप्ति प्राप्त करना है। राजस्थान सहित किसी विशेष राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में लाभार्थियों की वास्तविक कवरेज संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन है। अभियान के तहत राजस्थान राज्य सरकार के प्रस्तावों के आधार पर बांसवाड़ा और इंगरपुर जिलों में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित गतिविधियों का विवरण अनुलग्नक-II में है। इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार,

बांसवाड़ा और इंगरपुर जिलों के कुल 1698 गांवों में से 149 गांवों को पेयजल आपूर्ति के लिए संतृप्त किया जा चुका है। शिक्षा मंत्रालय ने बांसवाड़ा जिले में 3 छात्रावास और इंगरपुर जिले में 4 छात्रावास स्वीकृत किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बांसवाड़ा जिले में 27789 आवास और इंगरपुर जिले में 19582 आवास स्वीकृत किए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बांसवाड़ा जिले में 7 आंगनवाड़ी केन्द्र और इंगरपुर जिले में 3 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए हैं।

(घ) यह अभियान 2 अक्टूबर, 2024 को शुरू किया गया है और यह 2024-25 से 2028-29 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए है, जिसका बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये) है।

"प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अन्तर्गत आने वाले गांव" के संबंध में दिनांक 20.03.2025 को श्री राजकुमार रोट द्वारा उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3224 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत गांवों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार कवरेज

क्र. सं.	राज्य का नाम	गांवों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	878
2	अरुणाचल प्रदेश	329
3	असम	3161
4	बिहार	771
5	छत्तीसगढ़	6691
6	गोवा	25
7	गुजरात	4265
8	हिमाचल प्रदेश	270
9	जम्मू और कश्मीर	393
10	झारखंड	7139
11	कर्नाटक	1089
12	केरल	89
13	लद्दाख	143
14	लक्षद्वीप	2
15	मध्य प्रदेश	11377
16	महाराष्ट्र	4975
17	मणिपुर	516
18	मेघालय	1437
19	मिजोरम	383
20	नागालैंड	608
21	ओडिशा	7667
22	राजस्थान	6019
23	सिक्किम	119
24	तमिलनाडु	248
25	तेलंगाना	924
26	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	76
27	त्रिपुरा	392
28	उत्तर प्रदेश	517
29	उत्तराखंड	128
30	पश्चिम बंगाल	3212
कुल		63843

"प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अन्तर्गत आने वाले गांव" के संबंध में दिनांक 20.03.2025 को श्री राजकुमार रोट द्वारा उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3224 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राजस्थान राज्य सरकार के प्रस्तावों के आधार पर बांसवाड़ा और इंगरपुर जिलों में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित गतिविधियों का विवरण

(i) छात्रावासों का निर्माण:

(राशि लाख में)

क्र.सं.	जीर्ण-शीर्ण आश्रम छात्रावास का नाम	ज़िला	स्वीकृत निधि
1	राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास नरवाली, पंचायत समिति घाटोल	बांसवाड़ा	275.00
2	राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास रूप जी का खेड़ा, पंचायत समिति घाटोल	बांसवाड़ा	275.00
3	राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास रामगढ़, पंचायत समिति बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	275.00
4	राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास तलवाड़ा, पंचायत समिति तलवाड़ा	बांसवाड़ा	275.00
5	राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास बागीदौरा, पंचायत समिति बागीदौरा	बांसवाड़ा	275.00

(ii) शौचालय ब्लॉकों का निर्माण

क्र.सं.	आवासीय विद्यालय का नाम	ज़िला	इकाई	स्वीकृत निधि
1	बालिका आवासीय विद्यालय हरेंगजी का खेड़ा, घाटोल (क्षमता 270)	बांसवाड़ा	1	20.00
2	बालिका आवासीय विद्यालय सागवाड़ा (क्षमता 270)	इंगरपुर	1	20.00
3	बालक मॉडल पब्लिक स्कूल सुरपुर इंगरपुर (क्षमता 350)	इंगरपुर	1	20.00

(iii) बांसवाड़ा और इंगरपुर जिले में जिला स्तरीय एफआरए प्रकोष्ठों को भी मंजूरी दी गई है।
